

शारदीय नवरात्र: तीसरा दिन

मां चंद्रघंटा

नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र संशोभित है। मां चंद्रघंटा साहस ,धैर्य व शांति की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भय दूर होने और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है।

मंत्र
ओम देवी चंद्रघंटायै नमः॥
स्तुति
पिंडजप्रवारूढा चंडकोपास्त्रकेर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता॥
अर्थ: सिंह पर विराजमान, अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली मां चंद्रघंटा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मां की अराधना से साहस, शक्ति व सुख- शांति प्राप्त होती है।

पाकिस्तान में रहमान बाबा एक्सप्रेस के सभी 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 6 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा घायल

लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब में मंगलवार तड़के एक्सप्रेस ट्रेन बेपटरी हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि मुल्तान में शेर शाह ब्रिज के पास रहमान बाबा एक्सप्रेस के सभी 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेल हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
घायलों को इलाज के लिए मुल्तान के निशत्र अस्पताल ले जाया गया, जबकि बचाव दल दुर्घटना स्थल पर तैनात है। जियो न्यूज ने एक यात्री से बातचीत के आधार पर कहा कि यह हादसा सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। रेस्क्र्यू 1122 (बचाव दल टीम) के अधिकारी मुहम्मद अरशद ने अंग्रेजी दैनिक डॉन को बताया कि इस घटना में 49 लोग घायल हुए हैं और बचाव अभियान चल रहा है।
डॉन से बात करते हुए ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उन्होंने कहा, सिम्ल क्लियर था, और जब मैं शेर शाह स्टेशन इलाके से गुजर रहा था, तो मुझे अचानक एक झटका महसूस हुआ। ब्रेक लगाए और ट्रेन को रोकने में कामयाब रहा। फिर जब मैं इंजन से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि यात्री कोच पटरी से उतर गए थे और पटरी से दूर पड़े थे। यह खौफनाक था।

ओझा- गुनी व तंत्र-मंत्र के शक में भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर की दो सगी बहनों की हत्या

मेट्रो रेज
जमशेदपुर: जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड की रावताड़ा पंचायत के बबईदा गांव में एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं के शक में एक कलयुगी भाई ने अपनी ही दो सगी बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।
क्या है मामला: पुलिस और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी स्वरूप टुडू ने रविवार की रात अपने गांव में ओझा-गुणी को बुलाया था। इसी पूजा-पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उसने अपनी दोनों बहनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। अनुष्ठान और पूजा-पाठ संपन्न होने के बाद जब दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तब आरोपी ने कुल्हाड़ी से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस भीषण हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान: इस घटना में जान गंवाने वाली दोनों सगी बहनों की पहचान लक्ष्मी मुंडी (उम्र लगभग 50 वर्ष) जिनका विवाह धालभूमगढ़ प्रखंड के बासाझोर गांव में हुआ था और दुलारी सोरेन (उम्र लगभग 52 वर्ष) जिनका विवाह घाटशिला प्रखंड के चड़ईगोड़ा गांव में हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही धालभूमगढ़ थाना प्रभारी धीरज कुमार तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ने किया संरंडर: दूसरी ओर, आरोपी स्वरूप टुडू ने वारदात के तुरंत बाद खुद धालभूमगढ़ थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

सीजेआई को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग

(एससीएओआरए) ने भी सीजेआई के इस्तीफे की मांग वाले बयानों की निंदा की थी और चेतावनी दी थी कि ऐसी टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर करती हैं और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं। बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने सोमवार को चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर के प्रक्रिया के खिलाफ मार्च किया था। इसके बाद विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी सूची संशोधन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर की थी। इस मामले में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई घटना को लेकर भी संपर्क किया है, जब राहुल गांधी सहित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए रजिस्ट्री पहुंचे थे। जब वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया, तो सीजेआई ने पूछा, क्या यह मेशनिंग लिस्ट में है? भाटिया के ना कहने पर सीजेआई ने कहा, कल मेशन करना।

मां रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के तहत मुख्यमंत्री कर रहे हैं पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन

मेट्रो रेज
रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपनी पूजनीय दिवंगत माता स्व। रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के तहत पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास पर अपनी पूजनीय माता स्व। रूपी सोरेन की स्मृति में उन्हें दातुन, पानी और भोजन परोसने की पारंपरिक रस्म निभाई। उन्होंने अपने स्थानीय पारिवारिक, सामाजिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप अपने परिवारजनों के साथ यह रस्म निभाई। साथ ही माता स्व। रूपी सोरेन के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धा व सम्मानपूर्वक याद किया।

प्रधानमंत्री मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयानों से संबंधित है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर कमांडर इन थीफ और चोरों के सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दिया आदेश: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी द्वारा बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएएलपी) पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम निर्देश पारित किया। इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में जारी मानहानि की प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता पक्ष को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। चार सप्ताह में मांगा जवाब, तब तक ट्रायल कोर्ट में केस की कार्रवाई ठप: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने अपने निर्देशों में साफ किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, तब तक निचली अदालत के समक्ष चल रही सभी कार्यवाहियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस कानूनी राहत से राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी और आगे की कानूनी औपचारिकताओं से फिलहाल फौरी सुरक्षा मिल गई है।

'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा- 'लोकतंत्र की जननी है भारत'

12 सालों में 4 गुना बढ़ी रिन्यूएबल एनर्जी, पीएम मोदी ने पेश किया नए भारत का विजन

नई दिल्ली/एजेंसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' को संबोधित करते हुए वैश्विक समुदाय को एक नई सोच अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी, डेटा, ज्ञान और इनोवेशन ही असली ताकत हैं। हालांकि, असली सवाल यह नहीं है कि यह ताकत किसके पास है, बल्कि यह है कि इसका इस्तेमाल किस दिशा में और कैसे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को अब 'कंट्रोल करने की ताकत' से आगे बढ़कर 'सक्षम बनाने की ताकत' की दिशा में काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और ज्ञान का इस्तेमाल कंट्रोल करने या मुकाबला करने के बजाय, हमें मिलकर काम करने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा, आज टेक्नोलॉजी ताकत है, डेटा ताकत है, ज्ञान ताकत है और इनोवेशन ताकत है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ताकत किसके पास है, बल्कि यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी से सिर्फ कुछ लोग आगे बढ़ेंगे या लाखों लोगों के लिए नए मौके बनेंगे? क्या ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों की ताकत रहेगा या सबकी क्षमता बढ़ाएगा? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है: 'सक्षम बनाने की ताकत'। कंट्रोल करने की ताकत से आगे बढ़कर, हमें सक्षम बनाने की ताकत चाहिए। मुकाबला करने की ताकत से आगे बढ़कर, हमें दूसरों को सफल होने में मदद करने की ताकत चाहिए। जीडीपी में 7।8 प्रतिशत की बढ़ोतरी: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7।8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का एक मजबूत जরিजा बना रहा है। उन्होंने कहा, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग 75 गीगावाट थी। आज यह लगभग 300 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि हमने क्षमता को लगभग चार गुना बढ़ा लिया है। दोस्तों, भारत में हो रहा यह ऊर्जा बदलाव नए अवसर भी पैदा कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है: देश की भाषाई विविधता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा, 11।दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएँ, लगभग 80,000 रजिस्टर्ड अखबार और प्रकाशन, और 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूयू-ट्यूब यूजर्स और 50 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे देश में अलग-अलग मुद्दों पर खुली बहस होती है और लोग अलग-अलग नजरियों पर चर्चा करते हैं। हाल के समय में इसमें डिजिटल शक्ति ने अहम भूमिका निभाई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया: पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के पास भले ही सत्ता हो, लेकिन उसका मकसद नागरिकों को सिस्टम पर निर्भर बनाना नहीं होना चाहिए। बल्कि, उसका मकसद नागरिकों को मजबूत और सशक्त बनाना होना चाहिए, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए, भारत ने पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है।

कांके में कृषि पदाधिकारी के घर पर डकैती, जेवरात-नकदी लेकर फरार हुए पांच हथियारबंद अपराधी

बंदूक की नोक पर रिंग रोड स्थित आवास पर सुबह-सुबह वारदात

मेट्रो रेज

रांची: राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। कफि थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कृषि विभाग के पदाधिकारी रामाशंकर प्रसाद के रिंग रोड स्थित आवास को निशाना बनाते हुए पांच की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी सुबह-सुबह घर में घुसे और हथियार के बल पर परिवार के सदस्यों को अपने नियंत्रण में लेकर गहने और नकदी



लूटकर फरार हो गए।
सुबह-सुबह घर में घुसे अपराधी: मिली जानकारी के अनुसार, घटना कफि थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित रामाशंकर प्रसाद के आवास की है। सुबह के समय पांच अपराधी घर में दाखिल हुए। अपराधियों के हाथों में हथियार होने के कारण घर में मौजूद लोग भयभीत हो गए। इसके बाद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गहने और नकदी अपने कब्जे में ले ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिन की शुरुआत में ही इस तरह की वारदात से स्थानीय

लोगों के बीच भी चिंता का माहौल है।
वारदात के बाद जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलने के बाद कफि थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस लूट की पूरी घटना का पता लगाने और अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास में है। जांच के दौरान अपराधियों की पहचान, उनके फरार होने के रास्ते और लूटे गए सामान के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती: कृषि विभाग के पदाधिकारी के आवास पर हथियार के बल पर

हुई इस लूट की घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस के सामने अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और लूटे गए गहने व नकदी बरामद करने की चुनौती है। फिलहाल, लूटे गए सामान की कुल कीमत, घटना के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी तरह की मारपीट हुई या नहीं तथा अपराधियों की पहचान से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

पलामू : 22 वर्षीय युवक की मौत, गांव में पसरा मातम

मेट्रो रेज

पलामू: जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामघाट जोड़ा गांव में मंगलवार की सुबह एक 22 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी राजेश्वर मांझी के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।



परिजनों ने सुबह दी घटना की जानकारी: प्राच जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब तीन बजे रोहित कुमार की मानसिक तनाव के बीच मौत हो गई। सुबह जब घर के अन्य सदस्य सोकर उठे, तो उन्होंने रोहित को घर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। इसके बाद परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे।
पुलिस को दी गई सूचना: घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना सतबरवा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की ओर से घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
मौत के कारणों की जांच जारी: फिलहाल रोहित कुमार की मौत के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मानसिक तनाव की बात सामने आई है, लेकिन इसके वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना से गांव में शोक का माहौल है।



Government of Jharkhand
Department of Mines & Geology
Directorate of Geology
Engineer's Hostel No-2, 2nd Floor, Dhurwa, Ranchi

CORRIGENDUM
Short Tender Corrigendum Notice no. 01/2026-27 was published on 01.10.2026 in different News Papers vide PR. No.-390883. The following changes are hereby made in the said tender: -

Sl. No.	Particulars	
1	Last date of submission of Bid/NIT	23.10.2026 till 5.00 P.M.
2	Bid/NIT opening date	To be notified.

All other terms and conditions of the above-mentioned NIT shall remain unchanged. All prospective bidders are advised to visit the official website of the Government of Jharkhand, www.jharkhand.gov.in, for further updates and to submit their bids accordingly.

Sd/-

Director, Geology
Directorate of Geology,
Department of Mines & Geology,
Government of Jharkhand

PR 391624 (Mines and Geology) 26-27 (D)

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राँची।
सर्वसाधारण के लिए सूचना।



नाम-रूपाली सिंह, उम्र-22 वर्ष, उँचाई-5 फीट, रंग-गोरा, पहनावा-पिक रंग का कुर्ती एवं जींस पहनी हुई है।

उपरोक्त लापता महिला रूपाली सिंह, उम्र-22 वर्ष, पिता-सुरील कुमार सिंह, पता-लार्डन टैंक रोड, मनोकामना हनुमर मंदिर, काटार नं०-14 / 16 सी०, थाना-कोतवाली, जिला-राँची जो दिनांक-08.10.2026 को अपने घर से बगीर बताए कहीं घली गई जो आजतक अपने घर वापस नहीं आई है। जिसके संबंध में कोतवाली धाना सनहा सं०-27 / 2026, दिनांक-08.10.2026 दर्ज कर इनकी खोजबीन की जा रही है। उपरोक्त सूचना को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है।

अतः सभी जनसाधारण से अनुरोध है कि यदि उपरोक्त लापता महिला कहीं मिलती / दिखती है तो इसके संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में या निम्नांकित फोन नम्बर पर संपर्क कर इसकी सूचना दें।

Email ID(mc-deb@jhpolice.gov.in)

पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, राँची।	-9431706158
धाना प्रभारी, कोतवाली, राँची।	-9431706188
आयटक प्रेम कुमार सिंह।	-9241187297

PR- 391634 Police(26-27)D

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिमडेगा

(सर्वसाधारण के लिए सूचना)

लापता पुरूष सिलब्रियुस समद, उम्र-करीब 38 वर्ष, पे०-सिलवेस्तर समद, सा०-रैसिया जितियाटोली, थाना-कोलेबिरा, जिला-सिमडेगा, राज्य-झारखण्ड गोवा में रहकर काम कर रहे थे। दिनांक-30. 09.2026 को इनके छोटे भाई एलेक्सियुस समद के द्वारा मोबाइल के माध्यम से सूचना दिया गया कि सिलब्रियुस समद अचानक लापता हो गये है। सिलब्रियुस समद अबतक अपने घर वापस नहीं आया है और न ही उनसे किसी प्रकार का सम्पर्क हो पा रहा है। उक्त लापता पुरूष की बरामदगी अभी तकनहीं हो पायी है,जिसकी विवरणी निम्नवत है:-



हुलिया की विवरणी :-
लिंग :-पुरूष।
उम्र :-38 वर्ष।
रंग :-सांवला।
उँचाई :-05 फीट 05 इंच।
भाशा :-सामदरी एवं हिन्दी।
पहनावा :-हाफ पैट एवं शर्ट।
बाल:- सामने से उड़ा हुआ।
पहचान:- दोनो पैर जले हुए है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त लापता पुरूष के बारे मे पता चलता है तो नीचे अंकित दूरभास नं० पर अविलंब सूचित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा -	मोबाइल नं०-9431116444
पुलिस उपाधीक्षक, (मु०) सिमडेगा-	मोबाइल नं०-9431706227
धाना प्रभारी, कोलेबिरा -	मोबाइल नं०-9431706235
पुलिस निबंधन कक्ष, सिमडेगा -	मोबाइल नं०-9262998531

मानव तस्करी संबंधी टोल फ्री नं०-मोबाइल नं०-1800-3456-256

पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा

PR 391549 (Simdega)26-27'D

सीएमपीडीआईएल ने झारखंड में निःशुल्क कटे होंट और तालू की सर्जरी के लिए की साझेदारी

सीएसआर परियोजना हेल्दी स्माइल्स, हेल्दियर टुमॉरो के तहत 200 बच्चों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी



मेट्रो रेज

रांची: भारत में कटे होंट और तालू के इलाज के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था, एनजीओ स्माइल ट्रेन इंडिया ने झारखंड में बच्चों को निःशुल्क सर्जरी और इलाज की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के साथ साझेदारी की है। सीएमपीडीआईएल, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत सीएमपीडीआईएल ह्यहेल्दी स्माइल्स, हेल्दियर टुमॉरोह परियोजना को सहयोग देगा। इस पहल का उद्देश्य झारखंड में कटे होंट और तालू के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को समय पर बेहतर और पूरी तरह निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है।

इस परियोजना के तहत झारखंड के 200 बच्चों के कटे होंट और तालू की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। साथ ही, परिवारों को इस समस्या और इसके निःशुल्क इलाज के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए राज्य के पाँच जिलों-रांची, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और लातेहार-के साप्ताहिक हाट-बाजारों में ऑडियो संदेशों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों तक भी निःशुल्क इलाज की

जानकारी पहुँच सके और जरूरतमंद बच्चों को इलाज से जोड़ा जा सके। इसके अलावा, झारखंड के सभी 24 जिलों के जिला अस्पतालों में स्माइल ट्रेन और सीएमपीडीआईएल के संयुक्त जागरूकता बैनर लगाए जाएंगे। इनका उद्देश्य कटे होंट और तालू की समय पर पहचान और उपलब्ध इलाज के बारे में लोगों को जानकारी देना है।

इस साझेदारी पर स्माइल ट्रेन इंडिया की हेड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, अंजलि कटोच ने कहा, हम सीएमपीडीआईएल के आभारी हैं कि उन्होंने झारखंड के बच्चों और परिवारों तक बेहतर और निःशुल्क इलाज पहुँचाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाया है। कटे होंट और तालू का इलाज संभव है, लेकिन जानकारी की कमी और इलाज तक पहुँच न होने के कारण आज भी कई बच्चे, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे, समय पर इलाज नहीं करवा पाते। यह साझेदारी केवल 200 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इलाज की जानकारी मिले और जरूरतमंद बच्चे सही समय पर अस्पताल पहुँच सकें। सीएमपीडीआईएल के सहयोग से हम झारखंड में इलाज तक पहुँच को और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि कटे होंट और तालू के साथ जन्म लेने वाले अधिक से अधिक बच्चे स्वस्थ जीवन जी सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

अनिल शर्मा, सुरेंद्र बंगाली और फहीम खान समेत 53 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव खारिज

रांची: झारखंड सरकार ने गैंगस्टर अनिल शर्मा, सुरेंद्र बंगाली और धनबाद के फहीम खान समेत राज्य के 53 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये सभी कैदी राज्य की अलग-अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। राज्य सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक में इन कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी। जानकारी के अनुसार, गत 30 जुलाई को आयोजित राज्य सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक में 53 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को खारिज करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद गृह विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद फिलहाल इन कैदियों को रिहाई नहीं मिल सकेगी।

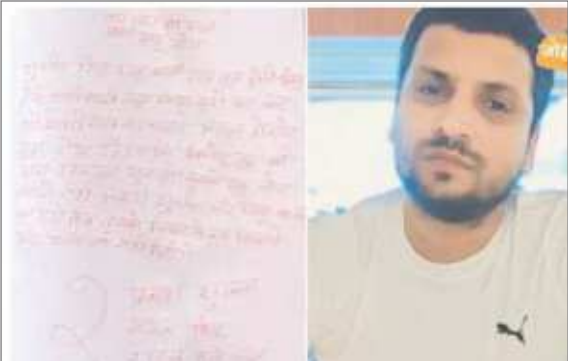
दुर्गा पूजा पर रांची सदर अस्पताल अलर्ट, 20 अतिरिक्त बेड और चार एंबुलेंस की व्यवस्था

रांची: रांची सदर अस्पताल ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थिति के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सदर अस्पताल में 20 अतिरिक्त बेड तैयार किया गया है, ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा चार अतिरिक्त एंबुलेंस तैयार रखी जाएंगी। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक विमलेश सिंह के अनुसार, 17 से 20 अक्टूबर तक अस्पताल अलर्ट मोड में रहेगा। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। सिविल सर्जन कार्यालय ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया है। थानी आदेश के मुताबिक, रांची के अलबर्ट एक्का चौक, कोकर में सदर धारा के पास और कचहरी चौक स्थित नगर नियंत्रण कक्ष के पास मेडिकल कैप लगाए जाएंगे। इन कैपों में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाएँ उपलब्ध रहेंगी।

मेट्रो रेज

रांची : राजधानी रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र अंतर्गत छपर गांव में बालू कारोबार को लेकर तनाव की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव में बालू लोडिंग के दौरान लगे एक लोडर (जेसीबी) में आग लगाने और कई राउंड गोली चलने की घटना का दावा किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल होने की बात कही जा रही है।

बालू लोडिंग के दौरान हुई घटना : जानकारी के मुताबिक, छपर गांव में बालू लोडिंग से जुड़े मामले के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी क्रम में एक लोडर (खड्ड) में आग लगाए जाने और करीब 8 से 10 राउंड गोली चलने की बात सामने आई है। घटना की खबर फैलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनने की सूचना है।



हालांकि, घटना से संबंधित सभी तथ्यों और नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।

राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी: इस घटना के बाद राहुल दुबे गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। उक्त पोस्ट में कथित तौर पर घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया

गया है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई कथित रूप से फोन कॉल को नजरअंदाज करने के कारण की गई। हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए दावे अपने आप में घटना में किसी गिरोह की संलिप्तता का प्रमाण नहीं हैं। पोस्ट की सत्यता और घटना से उसके संबंध की पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच के बाद ही हो सकती है।

बालू कारोबार से जुड़े लोगों

रांची विश्वविद्यालय के 41 सहायक प्राध्यापकों को 11 महीने का सेवा विस्तार

रांची : रांची विश्वविद्यालय ने विभिन्न पीजी विभागों और कॉलेजों में वोकेशनल और स्वचित्रपोषित पाठ्यक्रमों के तहत काम करने वाले 41 सहायक प्राध्यापकों को 11 महीने का सेवा विस्तार दिया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह सेवा विस्तार 19 सितंबर 2026 से लागू माना जाएगा।

आईएमएस के छह शिक्षकों को मिला विस्तार: इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस) के छह शिक्षकों को दोबारा नियुक्त किया गया है। इनमें डॉ। मनीषा कुमारी, डॉ अमित शेखर तिकी, डॉ नलिन रंजन त्रिपाठी, डॉ शिल्पी आभा खलखो, डॉ सोनी कुमारी और डॉ पूजा कुमार शामिल हैं।

स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में संतोष उरांव को सेवा विस्तार दिया गया है। वहीं, केओ कॉलेज, गुमला के बीसीए विभाग में डॉ अमित कुमार और सिमडेगा कॉलेज के बीसीए विभाग में कौशिक कुमार का पुनर्नियोजन किया गया है।

आश्वासन से नहीं माने छात्र, ट्रिपल आईटी में निदेशक के इस्तीफे की मांग तेज

संवाददाता

रांची: खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित रांची ट्रिपल आईटी में छात्र आदित्य की मौत के बाद विद्यार्थियों का आंदोलन मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। निदेशक राजीव श्रीवास्तव के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं हॉस्टल के बाहर तिरपा लगाकर धरने पर बैठे हैं। सोमवार की रात भी विद्यार्थियों ने धरनास्थल पर गुजारी। पिछले तीन दिनों से संस्थान के छात्र-छात्राएं प्रबंधन के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं और खेलगांव हाउसिंग सोसाइटी स्थित हॉस्टल के नीचे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मंगलवार को छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने कैपस पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए निदेशक राजीव श्रीवास्तव का इस्तीफा मांगा और पुलिस-प्रशासन से इस मामले में



छात्रों से शांतिपूर्वक संवाद करने की अपील करे।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक निदेशक प्रो राजीव श्रीवास्तव को हटया नहीं जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान में पिछले कई माह से लापरवाही बरती जा रही है, बार-बार शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छोटी-छोटी चीजों के लिए हम छात्रों को जेबें ढीली करनी पड़ती है जबकि प्रतिवर्ष हमलोग चार

लाख रुपये पढ़ाई के अलावा अन्य मदों में यहां फीस के तौर पर देते हैं। इसके बावजूद हमें लचर व्यवस्था के शिकार होना पड़ता है। बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल परिसर में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर निदेशक को हटाने की मांग कर रहे हैं। डाक्टरेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े छात्र: सोमवार की शाम करीब सात बजे संस्थान के बोर्ड ऑफ गर्वנס के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एके

भट्ट, निदेशक प्रो राजीव श्रीवास्तव समेत फैकल्टी और स्टाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और निदेशक को हटाने की मांग पर अड़े रहे।

खेलगांव चौक जाम करने की चेतावनी: छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने खेलगांव चौक जाम करने की भी चेतावनी दी है। फिलहाल छात्र हॉस्टल के बाहर धरने पर उठे हैं और निदेशक के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। आदित्य बिहार के पूर्णिया जिले का निवासी था। उसकी मौत के बाद संस्थान की आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, छात्रावास प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रबंधन छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।



सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

टेक दिग्गजों से पक्ष-विपक्ष दोनों रहें सावधान

सूचना प्रौद्योगिकी जिस तेजी से विकसित हो रही है उसी तेजी से इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। यह तकनीक जहां बड़ी आबादी को लाभ पहुंचा रही है, वहीं इसे नियंत्रित करने वाली चंद कंपनियों को बेशुमार ताकत भी सौंप रही है। इतनी कि ये कंपनियां राजनीतिक शक्तियों को भी बौना समझने लगी हैं। जहां बात नहीं बनती, वहां वे राष्ट्रीय नेतृत्व की साख बिगाड़ने में लग जाती हैं। कुछ देशों में सरकारें बनाने-गिराने के खेल में सक्रिय रहकर स्वार्थ साधना तो उनका पुराना नुस्खा है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और स्टारलंक के मालिक एलन मस्क का भारत सरकार पर किया गया अपनी तरह का 'पहला हमला' इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर मस्क ने कहा कि स्टारलंक को 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस मिल चुका है और उसने पांच वर्षों तक भारत के हर कानून का पालन किया, फिर भी लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं? यह बात पूरी तरह सच नहीं है। सरकार ने साफ किया कि स्टारलंक को मई 2025 में ही लाइसेंस मिल चुका है। सिर्फ स्पेक्ट्रम आवंटन अटका है, क्योंकि विदेशी निवेश की मंजूरी और सुरक्षा शर्तों का परीक्षण बाकी है। स्टारलंक ने जमीनी ढांचा विकसित करने के लिए जियो और भारती एयरटेल से साझेदारी भी की है और जियो के मालिक मुकेश अंबानी ही हैं। तो अंबानी पर कटाक्ष का अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है कि मस्क सुरक्षा शर्तों में ढील चाहते हैं और यह भी कि सैटेलाइट फोन के क्षेत्र में कोई भारतीय कंपनी उनके मुकाबले आगे न बढ़े, क्योंकि अंबानी भी यह महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे समय, जब केंद्र सरकार नीट और एसआइआर पर घरेलू राजनीति में घिरी है, मस्क की टिप्पणी मौके का फायदा उठाने की चाल है। ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस सोची-समझी चाल पर बिना सोचे प्रतिक्रिया दे दी- 'भारत में स्वागत है एलन, जब तक दूसरा शख्स न मिले इंतजार करें।' जबकि, स्टारलंक के जियो और एयरटेल से समझौते पर तब कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। घरेलू मोर्चे पर सरकार को घेरना एक बात है और अंतरराष्ट्रीय दांव-पेचों में शामिल होना दूसरी। क्या सुरक्षा की चिंता किए बिना किसी सैटेलाइट कंपनी को इसलिए मंजूरी दे देनी चाहिए कि उसके मालिक अंबानी-अदाणी नहीं, मस्क हैं? दूसरी बात यह है कि विदेशी कंपनी के आगे भारतीय कंपनी को तरजीह क्यों नहीं मिलनी चाहिए, भले ही वह अंबानी या अदाणी की ही क्यों न हो, जिनकी मोनोपॉली विपक्ष के लिए घरेलू मुद्दा है? मस्क जैसे लोग नई तकनीकों से मानवता की भलाई के लिए भले ही ढेरों काम कर रहे हों, पर इससे शायद ही कोई इनकार करे कि आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के टकराव में उनका व्यवहार पराया ही रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ऐसे तकनीकी महारथियों से सावधान रहना होगा, न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी।

हवाई टिकटों के दाम की तय हो अधिकतम सीमा

एक दौर में विलासितापूर्ण समझे जाने वाला हवाई सफर आज आम आदमी की भी अहम जरूरतों में शामिल हो गया है। इसकी वजह यही रही है कि लोगों का आर्थिक स्तर तो बढ़ा ही है, समय के साथ-साथ हवाई यात्रा सेवाओं का भी खूब विस्तार हुआ। इसीलिए यह कहा जाने लगा है कि हवाई यात्रा अब सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं रह गई है। इस तथ्य के बावजूद प्रमुख त्योहारों व छुट्टियों के मौकों पर तो हवाई यात्रा की पहुंच सक्षम लोगों तक ही पहुंचती नजर आती है। संकट उनके सामने भी है, जिन्हें आपात स्थिति या मजबूरी के कारण न चाहते हुए भी हवाई यात्रा को आखिरी विकल्प के रूप में चुनना पड़ता है। किराया निर्धारण की नियामक व्यवस्था नहीं होने से देश के प्रमुख घरेलू हवाई मार्गों पर हर साल की तरह इस बार भी त्योहार के मौके पर हवाई टिकटों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। विमानन कंपनियों की मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि त्योहार के मौकों पर पिछले साल के मुकाबले हवाई यात्रा का किराया तीस से चालीस फीसदी तक बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कुछ मार्गों पर तो अब तक मिलने वाले टिकट के दाम भी बढ़कर तीन गुणा तक पहुंच गए हैं। किसी भी सेवा या वस्तु की मांग अधिक होने पर उसके मनमाने दाम बढ़ाना वस्तुतः उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन चिंता इस बात की है कि न तो सरकार को उपभोक्ताओं के इस अधिकार की चिंता है और न ही विमानन कंपनियों को। दरअसल, अपनी सुविधा के अनुसार लाभ-हानि का हिसाब लगाने वाले तंत्र से तो किसी संवेदनशीलता की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। यही वजह है कि एक ही दिन और एक ही रूट पर अलग-अलग विमान कंपनियों के हवाई टिकट के दाम अलग-अलग नजर आते हैं। कंपनियों की मनमानी और सरकार की अनदेखी से यात्रियों की जमकर जेब ढीली हो रही है। त्योहारों, छुट्टियों के दौरान और उड़ान के ऐन पहले हवाई किराया बढ़ने का तथ्य कोई नया नहीं है। सामान्य दिनों में भी किराये से जुड़ा विमानन कंपनियों का एल्गोरिदम मॉड और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। ऑनलाइन सिस्टम में बार-बार सर्च करने से किसी भी रूट पर मांग बढ़ती नजर आती है और टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। ईंधन के दाम बढ़ने व सुविधाओं में विस्तार पर तर्कसंगत वृद्धि तो ठीक है लेकिन मनमानी वृद्धि को सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के दौरान यात्रियों के शोषण की संज्ञा दे चुका है।कोर्ट के निर्देश पर सरकार इस दिशा में नियम-कायदे बनाने की बात जरूर कर रही है लेकिन नियम-कायदे बने उससे पहले प्रत्येक घरेलू विमान सेवा में किराये की अधिकतम सीमा (कैप) लागू करना ही इस दिशा में राहत का कदम हो सकता है। इंडिगो संकट के दौरान सरकार ऐसा कर चुकी है लेकिन यह व्यवस्था अल्पकालिक न होकर स्थायी करने की जरूरत है।

चुनाव आयोग विवाद से बड़ी सियासी तपिश

ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली तथा एसआइआर पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई फैसला सुनाने से तो परहेज किया, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया कि उसने फॉर्म-6 में किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी।

राजकुमार सिंह	
	
चुनाव आयुक्तों की ओर से दस महीने में 14 बार आपत्तियों के मीडिया में खुलासे के बाद निशाने पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विभिन्न संगठनों के सड़क पर उतरने, पूर्व नौकरशाहों द्वारा महाभियोग एवं आरोपपत्र जारी करने और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से सरकार भी सवालों से घिर गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय दोनों आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी की संयुक्त बैठक की तस्वीर और 'आयोग में सब कुछ ठीक' होने के दावे वाली प्रेस रिलीज ही जारी कर पाए, जिससे जवाब कम मिले, 'सुधारात्मक कदमों' से संदेहों को बल ज्यादा मिला।	
परिणामस्वरूप कॉर्कोरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से लेकर विपक्ष तक तमाम संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे, एसआइआर से पहले की मतदाता सूची बहाल करने और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर सड़क पर हैं। सीजेपी ने मुंबई के शिवाजी पार्क से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणा की है तो 'ईंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने भी दो अक्टूबर से व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया है। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावत एक अंग्रेजी अखबार के खुलासे से उत्साहित 'ईंडिया'	

गठबंधन अपने आरोपों को लेकर राष्ट्रपति के पास भी जाएगा और संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग भी लाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून की वैधता के साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है। ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली तथा एसआइआर पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई फैसला सुनाने से तो परहेज किया, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया कि उसने फॉर्म-6 में किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट का रुख तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, बैठकों के एजेंडा और उनकी मिनट्स की समीक्षा पर निर्भर करेगा, लेकिन उसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष की निगाहें जन साधारण की प्रतिक्रिया पर ज्यादा रहेंगी। पेपर लीक मामले में सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर 'जेन जी' आंदोलन के चलते नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल में पहली बार अपने किसी मंत्री का इस्तीफा दिलवाने को मजबूर हुई। फिर भी दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर मंतर आंदोलनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी के सवाल पर सत्तापक्ष और विपक्ष की तनातनी में संसद का मानसून सत्र बह गया।

दोनों चुनाव आयुक्तों को बताए बिना मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा फैसले लेने के मीडिया में खुलासे से संसद के शीतकालीन सत्र से पहले

ही विपक्ष को उससे भी बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद से ही चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाते रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के बाद 'सरकार चोरी' में बदल गए। चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल भाजपा उन आरोपों को खारिज करते हुए इसी बीच कुछ विधानसभा चुनावों में विपक्ष की जीत को लेकर सवाल पूछते रहे, लेकिन दो चुनाव आयुक्तों द्वारा फॉर्म-6 समेत एसआइआर प्रक्रिया व चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति के खुलासे से विपक्ष के तेवर ज्यादा आक्रामक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी पिछली बार राहुल गांधी से आरोपों पर हलफनामा देने या माफी मांगने की मांग जैसी तल्खी नहीं दिखाई।

भाजपा ही उनका बचाव कर रही है। भाजपा का तर्क है कि चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विपक्ष उसकी सरकारों की वैधानिकता पर संदेह का माहौल बना रहा है, इसलिए उसे जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा संदेहास्पद ढंग से थोक में फॉर्म-7 जमा करवाने के खुलासे से भी वह कठघरे में है। दरअसल, चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर भी सार्वजनिक विमर्श में चिंताएं सामने आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट दो बार टिप्पणी कर चुका है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना ही

नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां व सवाल आयोग के साथ सरकार को भी कठघरे में खड़ा करते हैं। दरअसल दशकों तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिना किसी कानून के की जाती रही। नियुक्ति संबंधी कानून के अभाव में केंद्र सरकार की मनमर्जी रोकने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दो मार्च, 2023 को संविधान पीठ ने फैसला दिया कि इस बाबत संसद की ओर से कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर होगी। उसी साल 28 दिसंबर को संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें व कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित कर कानून बना दिया, जिसमें तीन सदस्यीय चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केबिनेट मंत्री को जगह दी गई। मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर केबिनेट मंत्री को शामिल करने से संदेश गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार बचस्व चाहती है। विपक्ष के तमाम संदेह और सवाल इसी संदेश से उपजे, जिन्हें आयोग के अंदरूनी विवाद से बल भी मिल गया है।

युवा शक्ति ही साकार करेगी विकसित भारत का सपना

सभी विद्यार्थियों से एक जैसी उपलब्धियों की अपेक्षा करना उचित नहीं है। किसी की रुचि विज्ञान में हो सकती है, तो कोई

साहित्य, संगीत, खेल, कला या उद्यमिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। विद्यार्थियों की तुलना दूसरों से नहीं होनी चाहिए ।

प्रो मनोज डोगरा

विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनकी आंखों में चलने वाले सपने, मन में उठने वाले विचार और कर्म में दिखाई देने वाला संकल्प ही देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासक, उद्यमी, सैनिक और राष्ट्रनिर्माता हैं। इसलिए विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारना, उन्हें सही दिशा देना और उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना केवल परिवार या शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। इसी संदर्भ में विश्व विद्यार्थी दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में 15 अक्तूबर को पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणास्रोत डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा, ज्ञान, अनुशासन, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करना है। डा. कलाम का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके पास बड़े सपने देखने का साहस और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करने का संकल्प हो।

डा. कलाम का जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा : डा. कलाम का जीवन संघर्ष, सादगी, अनुशासन और समर्पण की अनुपम मिसाल है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के प्रति अपनी लगन को कभी कम नहीं होने दिया। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद भी उनका सबसे प्रिय परिचय एक शिक्षक का ही रहा। डा. कलाम का विश्वास था कि

सुख की सही परिभाषा

राजयोगी ब्रह्माकुमार निकुंज जी

आज के युग में रहने वाले तथाकथित आधुनिक लोगों को अपने सोशल स्टेट्स अर्थात अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता रहती है। और इसी वजह से समाज की आंखों के सामने आज जिनके पास बड़ा घर, चमचमाती गाडियों का बेड़ा, शरीर को आराम देने वाले अति आधुनिक भौतिक साधन, नौकरों की फौज और पार्टियों, होटलों, सिनेमाघरों में आवागमन है, वह संपन्न एवं सुखी माने जाते हैं। बदकिस्मती से आज का मानव ऐशो आराम की इस भ्रामक धारणा में ऐंडी से चोटी तक जकड़ा

हुआ है और सुख के इन साधनों को जुटाने में वह दिन-रात एक कर रहा है। आज रोजमर्रा के सामान्य कामकाज स्वयं करने वाले व्यक्ति को अकसर यह अवॉखित सलाह मिलती है कि ह्यअरे, आप और यह कार्य! इन छोटे-मोटे कार्यों के लिए किसी नौकर को रख क्यों नहीं लेते? अपने दो पांवों रूपी मोटर साईकिल पर दौड़ने वालों को भी अकसर यह नसीहत मिल जाती है कि भाई एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, कब तक यूं ही पगडंडियां मापते रहोगे, अब तो तुम्हारे ऐशो आराम के दिन हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शरीर को आराम देने वाले सभी साधनों, उपकरणों, पदार्थों की उपस्थिति मात्र ही सुख का आधार है या सच्चे सुख का अर्थ इनसे कुछ भिन्न है? अवश्य ही सुख और शांति केवल शरीर को नहीं अपितु मन को भी चाहिए। क्योंकि मानव जीवन केवल शरीर नहीं

है परंतु आत्मा और शरीर के योग का अद्भुत मिश्रण है। अतः केवल शारीरिक ऐशो आराम के भौतिक पहलू पर ही ध्यान देना, जीवन को नरक सामान बनाने जैसा होगा। भारत के एक महानगर में रहने वाले अमीर शख्स को सभी के बीच में यह दावा करने की आदत थी कि उसके पास इतना धन है, जो उसकी 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने इसी धन के अभिमान में वह अपने जीवन को मौज-मस्ती और पार्टी बाजी करने में बिता रहा था और इस मौज मस्ती में उसने अपने अनेक यार-दोस्तों को भी भागीदार बनाया और वह सभी भी उसे ऐश के मामले में अपना आदर्श मानते थे, परंतु यह आदर्श रूपी पुतला उस समय चरमपर कर गिर पड़ा, जब मात्र 35 वर्ष की आयु में वह मधुमेह से पूरी तरह ग्रसित हो गया।

इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान तक पहुंच को आसान बना दिया है। आज घर बैठे दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयों ने सीखने के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, मोबाइल पर अनावश्यक समय बिताना, गलत सूचनाओं का प्रसार और डिजिटल मनोरंजन की लत विद्यार्थियों की एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। कई विद्यार्थी दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करके तनाव का अनुभव करते हैं और अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। तकनीक अपने आप में न अच्छी है और न बुरी, उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को डिजिटल साधनों का इस्तेमाल ज्ञान अर्जित करने, नई क्षमताएं विकसित करने और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। उन्हें यह भी सीखना होगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक जानकारी सत्य नहीं होती। तथ्यों की जांच करना, विश्वसनीय स्रोतों को पहचानना और अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करना आज की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा का दबाव : विद्यार्थियों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानसिक दबाव भी है। अच्छे अंक प्राप्त करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने और मनचाहा करियर चुनने की दौड़ में कई विद्यार्थी तनाव का सामना करते हैं। कुछ मामलों में अधिभावकों की अत्यधिक अपेक्षाएं और समाज में सफलता की सीमित परिभाषा इस दबाव को और बढ़ा देती है। यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग होती है। सभी विद्यार्थियों से एक जैसी उपलब्धियों की अपेक्षा करना उचित नहीं है। किसी की रुचि विज्ञान में हो सकती है, तो कोई साहित्य, संगीत, खेल, कला या उद्यमिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अधिभावकों और शिक्षकों को विद्यार्थियों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उनकी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल, विकसित भारत का सपना युवा पीढ़ी ही साकार करेगी।

आपके पत्र

बहुत जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य

दस अक्तूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन बहुत से देशों में सरकारी और विभिन्न सामाजिक संगठन लोगों को मानसिक तनाव से बचने के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य होना भी जरूरी है, तभी हम जिंदगी के मजे ले सकते हैं। हमारे देश में आज शारीरिक अस्वस्थ लोगों का आंकड़ा ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मानसिक रोगी भी बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगी होने के मुख्य कारण कई गिनवाए जा सकते हैं। संभावना है कि बहुत ही कम गरीब ऐसे होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य संकट के दायरे में आए होंगे। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के आंकड़े बढ़ने के कारण ही तो देश में आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं।

संध्या तिवारी,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वताधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रा्टी रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक :** लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवायों एवं दंडित परिवारों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 73699017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :** **www.metrorays.in****email :** **metrorays.ranchi@gmail.com**

प्रवासी मजदूरों को मिलेगा विस्थापन भत्ता, दुर्घटना में दो लाख तक की सहायता का प्रावधान



लातेहार : दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इसके तहत मजदूरों को विस्थापन भत्ता, आने-जाने का किराया और यात्रा के दौरान व्यतीत समय की मजदूरी देने की व्यवस्था है। वहीं, दुर्घटना, स्थायी अशक्तता और मृत्यु की स्थिति में निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले श्रमिकों का निबंधन कराना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

समझौते के दिन से देय होगी मजदूरी: प्रवासी मजदूरों को काम पर ले जाने के लिए एजेंट, सरदार या ठेकेदार के साथ जिस दिन समझौता या करार होगा, उसी दिन से मजदूरी देय होगी। इसके अलावा संबंधित संवेदक या एजेंट को आधे महीने की मजदूरी के बराबर विस्थापन भत्ता देना होगा। मजदूरों के आने-जाने का किराया और यात्रा में व्यतीत समय की मजदूरी का भुगतान भी संबंधित संवेदक, एजेंट या मुख्य नियोजक को करना होगा। मजदूरी और अन्य भत्तों के भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके बाद मुख्य नियोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। दूसरे राज्यों में काम कराने के लिए श्रमिकों को ले जाने वाले ठेकेदार के लिए श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

दुर्घटना या मृत्यु पर मिलेगी आर्थिक सहायता : प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अशक्तता होने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत पंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को दो लाख रुपये और अपंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

इसी तरह, दुर्घटना में दोनों आंखों या दो अंगों की हानि होने पर भी इतनी ही सहायता का प्रावधान है। वहीं, एक आंख या एक अंग की हानि होने पर पंजीकृत श्रमिक को एक लाख रुपये और अपंजीकृत श्रमिक को 75 हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था है।

सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृतक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास तक लाने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत विदेश में प्रवास के दौरान असायमिक मृत्यु होने पर निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले लाभभुक् के आश्रितों को पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। श्रमाधान पोर्टल पर करा सकते हैं निबंधन : प्रवासी श्रमिक अपने स्मार्टफोन के माध्यम से श्रमाधान पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र की भी सहायता ली जा सकती है। निबंधन के लिए आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान किसी तरह की समस्या, शोषण या सहायता की जरूरत होने पर प्रवासी निर्वंत्रण कक्ष से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

प्रवासी निर्वंत्रण कक्ष के नंबर:

9470132591

9431336427

9431336398

9431336472

9431336432

टोल फ्री नंबर: 18003456526

उपयुक्त ने श्रमिकों से की अपील : उपायुक्त संदीप कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने से पहले अपने अधिकारों और सरकार की ओर से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने श्रमिकों को निबंधन कराने तथा मजदूरी, भत्ते या कार्यस्थल पर किसी तरह की समस्या अथवा शोषण होने पर संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। प्रशासन के अनुसार, जागरूकता और निबंधन से जरूरत के समय श्रमिकों और उनके परिवारों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी।

जेएनयू प्रकरण के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने दिया धरना



साहिबगंज : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से जुड़े एक कथित प्रकरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी साहिबगंज जिला इकाई के तत्वावधान में भाजपा महिला मोर्चा ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी ललितला पासवान ने किया।धरना-प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव और जिला प्रभारी अमृत पांडेय विशेष रूप से उपस्थित रहे।धरना को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोप सही पाए जाने पर सांसद को सदस्यता रद्द करने की दिशा में कदम उठाना जाना चाहिए।उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अन्य मुद्दों पर मुखर रहते हैं,लेकिन इस प्रकरण पर कांग्रेस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। ललितला पासवान ने कहा महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में होनी चाहिए सख्त कार्रवाई कार्यक्रम प्रभारी एवं भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष ललितला पासवान ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा से जुड़े किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।कार्यक्रम में बड़हरवा नगर अध्यक्ष अर्पिता दास,पूर्व नगर अध्यक्ष श्यामल दास,जिला उपाध्यक्ष सोनेलाल ठाकुर,बापू निर्मल दास, संजीव गुप्ता सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

झारखंड

झिकटिया में 18 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पैडलर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

संवाददाता
साहिबगंज/बरहरवा : बरहरवा थाना क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की आपसी समव्यय से नशे के कारोबार करने वाले पर कड़ा प्रहार हुआ है जिससे नशे कारोबारियों में हड़कम्प मच गई है।

ब्राउन शुगर स्मैक डिलीवरी करने गए पैडलर को ग्रामीणों ने दबोचा,किया पुलिस हवाले रविवार की शाम बरहरवा थाना क्षेत्र के झिकटिया काली मंदिर के समीप रहने वाले शिवा कुमार 22 वर्ष पिता-स्व अशोक कुमार महतो ब्राउन शुगर बेचने के लिए झिकटिया चौक पहुँचा था ।चौक पर मौजूद ग्रमीणों को शक हुआ तो उसको पकड़ा गया और कड़ाई पूछताछ किया गया ,तो उसने बताया किसी युवक ने उसे फोन करके खरीदने के लिए बुलाया था जिससे ब्राउन शुगर डिलीवरी करने आया था तत्पश्चात ग्रमीणों ने तुरंत बरहरवा थाना प्रभारी रूपेश कुमार को फोन कर मामले की जानकारी दी।

पुलिस ने त्वरित सज्ञान लेते हुए वरीय पदाधिकरियों के निर्देश पर गश्ती दल में मौजूद

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने संभाला कार्यभार



अधिवक्ता संघ भवन में न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ देकर किया गया स्वागत

संवाददाता
साहिबगंज : सुभाष ने सोमवार को साहिबगंज व्यवहार न्यायालय में 20वें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में योगदान दिया। योगदान के बाद शाम चार बजे वे जिला अधिवक्ता संघ भवन पहुंचे,जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ललित स्वदेशी एवं सचिव विजय कर्ण ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया।विदित हो कि न्यायाधीश सुभाष वर्ष 2014 से 2016 तक

साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डीएलएसए के सचिव,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसीजेएम व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम के पद पर कार्यरत रहे थे।इसके बाद जिला व सत्र न्यायाधीश के पद पर पदेन्तित होने पर उनका स्थानांतरण जमशेदपुर हो गया था।वे वर्तमान में धनबाद के कुटुंब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।पदेन्तित के बाद उन्होंने साहिबगंज में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है।इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश,कुटुंब न्यायालय साहिबगंज संजय कुमार उपाध्याय,जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी एवं जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण उपस्थित थे।

झामुमो कार्यकर्ताओं ने रुपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि



संवाददाता
साहिबगंज : जिले के बोरियो प्रखंड स्थित मोरंग नदी स्थित आवास पर जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपाध्यक्ष संजीव शामू हेंब्रम और जिला सचिव सुरेश टुडू की के नेतृत्व में राज्य के जाक स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता जी स्वर्गीय रूपी सोरेन जी के निधन पर श्रधांजलि सह शोकसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दो मिनट का मौन

युवाओं को सुविधा मिलने का इंतजार विधायक प्रतिनिधि इरशाद मुन्ना ने जिला खेल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जल्द संचालन शुरू कराने की मांग

संवाददाता

चंदवा : प्रखंड के युवाओं को बेहतर फिटनेस सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से निर्मित जिम को चालू कराने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर विधायक प्रतिनिधि मो. इरशाद मुन्ना ने जिला खेल पदाधिकारी अनिमेष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर जिम का संचालन जल्द शुरू कराने की मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि चंदवा में जिम की सुविधा शुरू होने से



स्थानीय युवाओं को नियमित व्यायाम करने और अपनी शारीरिक फिटनेस

बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही, खेलकूद के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जब युवाओं के लिए जिम का निर्माण कराया गया है, तो इसका संचालन भी जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। जिन चालू होने से युवाओं को फिटनेस के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा और उन्हें व्यायाम के लिए अन्य स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

न्यूज ब्रीफ

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दाखिल, राहुल गांधी ने छेडी कानूनी जंग, अखिलेश संग 11 नेताओं ने किए दस्तखत



नई दिल्ली: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत द्वारा मुलाकात करने से इनकार करने और अदालत में अर्जी दायर करने की उनकी सलाह के बाद सोमवार की शाम सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर एक याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में वोटर लिस्ट के ह्यविशेष गहन पुनरीक्षणह्नु यानी एआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों लगाए गए हैं। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में वोट चोरी के आरोपों को लेकर एसआईआर पर रोक लगाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है। यह जनहित याचिका है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कुल 11 नेताओं ने दस्तखत किए हैं। याचिका पर दस्तखत करने वालों में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस (समता गुट) के नेता सीगत राॅव, शिवसेना के नेता संजय राउत और सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी, सीपीआई नेता डी राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा झामुमो सांसद महुआ माझी, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद शबीर का भी नाम शामिल है। इस याचिका में विपक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अब चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी प्रतिवादी बनाया है। याचिका में विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं और उसे रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई है।

अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम, केंद्र का निर्देश ब्लड टेस्ट से लेकर एक्स-रे तक दिखाने होंगे सारे चार्ज



नई दिल्ली: केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं और सुविधाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीज-केन्द्रित व्यवस्था को मजबूत करना है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इलाज व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े शुल्क की जानकारी मरीजों और उनके परिजनों को आसानी से दिखाई और उपलब्ध हो। मंत्रालय के अनुसार, उपचार शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिलने से मरीज और उनके परिवार इलाज पर होने वाले संभावित खर्च को पहले से समझ सकेंगे। इससे उन्हें बेहतर वित्तीय योजना बनाने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही बिलिंग को लेकर होने वाले भ्रम और विवाद भी कम होंगे तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

कांग्रेस, शिवजी की बारात नहीं, अराजकता फैलाने वाले हुड़दगियों की जमात है: शिवराज सिंह चौहान



नई दिल्ली: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगवाई में इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों और नेताओं ने सोमवार को बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। इस पर केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने तीखा तंज कसा है। चौहान ने इस कवायद को राहुल गांधी की नौटंकी करार दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी का प्रधान न्यायाधीश से मिलने के लिए उच्चतम न्यायालय तक मार्च करना नौटंकी है। उन्होंने इस बात पर भी तंज कसा कि जो लोग कल तक श्रीराम का विरोध करते थे, वह आज शिवजी की बात कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार का दोष निर्वाचन आयोग पर मढ़ती रही है, जबकि इसके लिए असल में उसका खुद का विचार-शून्य नेतृत्व जिम्मेदार है। शिवराज ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीजेआई) के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को शिव की बारात बनाने के लिए राहुल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह असल में गुंडों का समूह है, जो सड़कों पर अराजकता फैला रहा है।

तमिलनाडु से श्रीलंका तक समुद्र के रास्ते तस्करी की कोशिश नाकाम, 60 लाख के बीड़ी पत्ते जव्व

थूथुकुडी : तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में समुद्र के रास्ते श्रीलंका बीड़ी के पत्ते तस्करी करने की एक बड़ी कोशिश को क्यू ब्रांच पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने तटीय इलाके से लगभग 60 लाख रुपये कीमत के बीड़ी पत्तों से लदी एक लोड वैन को जब्त किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्करी मौके से फरार हो गए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्यू ब्रांच की इंस्पेक्टर विजया अनीता को गुप्त सूचना मिली थी कि तिरुचेट्टूर तालुक पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले वीरपांडियनपट्टिनम इलाके में सूर्या टिम्बर डिपो के उतर की तरफ स्थित तटीय क्षेत्र से नाव के जरिए श्रीलंका के लिए बीड़ी के पत्तों की तस्करी की तैयारी चल रही है।

इस इन्फुट के आधार पर क्यू ब्रांच की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी थी। गश्त के दौरान देर रात 2:40 बजे पुलिस को वीरपांडियनपट्टिनम में सूर्या टिम्बर डिपो के उतर में समुद्र तट की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संधिघ टाटा 407 लोड वैन खड़ी मिली।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एससी- एसटी कोटा बढ़ाने वाला कानून रद्द, 50% सीमा लांघना असंवैधानिक

बेंगलुरु : कर्नाटक में आरक्षण के दायरे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाले 2022 के कानून के प्रमुख प्रावधानों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने दो टूट शब्दों में कहा कि आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का किसी भी सूरत में उल्लंघन करना असंवैधानिक है। इस फैसले के साथ ही राज्य में कुल आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कदम को बड़ा झटका लगा है।

अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन, कोर्ट ने निरस्त कीं धारा 3 और 4: मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस के. एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने कानून



की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अधिनियम की धारा-3 और धारा-4 को रद्द कर दिया। अदालत ने रेखांकित किया कि शैक्षणिक

संस्थानों में दाखिले से जुड़ी धारा-3 कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाकर संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15 का सीधा उल्लंघन करती है। इसी तरह,

सरकारी सेवाओं और नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने से जुड़ी धारा-4 को भी असंवैधानिक करार देते हुए अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के मूल ढांचे के

खिलाफ है।

इंदिरा साहनी केस की नजीर, 50 फीसदी की लक्ष्मण रेखा बरकरार: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक हर्षादिरा साहनी बनाम भारत सरकारह्नु फैसले का प्रमुखता से हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने उस ऐतिहासिक फैसले में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय की थी, जिसे बाद के कई फैसलों में भी लगातार बरकरार रखा गया है। कर्नाटक सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में भी इसी कानूनी नजीर का आधार बनाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पारित इस कानून के जरिए अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया था, जिसे 11 जनवरी 2023

को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। सामाजिक न्याय पर पड़ेगा असर, डिप्टी सीएम ने पूर्व सरकार को घेरा: हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इसे बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला बताया। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण में वृद्धि रद्द होने का राज्य में सामाजिक न्याय, शैक्षणिक अवसरों और युवाओं की सरकारी नौकरियों पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार न्यायपालिका और संविधान का पूरा सम्मान करती है, लेकिन इस अदालती फैसले ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की राजनीतिक जवाबदेही और केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार अब इस कानूनी झटके के बाद अगले कानूनी विकल्पों और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।



एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसपी ने दिया निलंबित, विभाग में मचा हड़कंप

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एनडीपीएस एक्ट के एक अभियुक्त को पुलिस अधिश्ठा में ले जाने के दौरान हुई घटना के मामले में सहोदरा थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बेतिया पुलिस की ओर से सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सहोदरा थाना कांठ संख्या 65/25, दो अगस्त 2025 से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की गई है। निलंबित पुलिसकर्मियों में सहोदरा थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक रवि शंकर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार, सिपाही सीदागर कुमार यादव, राज किशोर ऋषि, कुंदन कुमार और चालक सिपाही सुमन कुमार शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चंपारण, बेतिया के आदेश पर सभी छह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मृतक की पहचान गुलजारपुर गांव निवासी मोनल कुमार राय के रूप में हुई है। वह सहार थाना क्षेत्र का रहने वाला था।

ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, केरल में सीईसी को हटाने के लिए प्रस्ताव पास

नई दिल्ली: वोट चोरी के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खडगे, अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए। यह पहली बार है, जब विपक्षी नेताओं ने किसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। करीब एक किमी लंबे मार्च में विपक्ष के नेता बस में, पैदल और वाहन में सवार हुए। पैदल मार्च के बाद राहुल गांधी, प्रियंका, खडगे के साथ अन्य विपक्षी सांसद सोमवार शाम को अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक पहुंच गए। विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और सुरक्षा कार्यों से छह मेट्रो स्टेशनों पर शाम चार बजे तक प्रवेश और निकास बंद रखे गए। उधर, दक्षिण भारतीय राज्य में ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ है।

केरल विधानसभा के प्रस्ताव में एसआईआर में कथित अनियमितताओं को दूर करने की मांग की गई है। खास बात है कि विपक्ष एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए पर वोटर चोरी के आरोप लगा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशनन ने लिखा कि केरल विधानसभा ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। हमारी चुनावी प्रक्रिया



की निष्पक्षता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट में बदलाव, गोंय मतदाताओं का नाम सूची से हटना और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जताई गई गंभीर चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ज्ञानेश कुमार अपराधी नहीं, उनसे गड़बड़ कराई जा रही: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की है। उनके सैसेज आते हैं। ज्ञानेश कुमार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आप अपराधी नहीं है, आपसे बस करवाया गया है। सबसे आसान रास्ता है कि इस्तीफा दो और रास्ते से हट जाओ। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने से पहले 30 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने कहा कि दिल्ली को जेल बना दिया गया है। ये पुलिस वाले कहना चाहते हैं कि इन तीनों नए चिन्हित स्थलों पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या मार्च के आयोजन को लेकर एक विस्तृत और संशोधित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जल्द ही अलग से जारी की जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान

आईएमएफ ने जताया 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान,दुनिया भर की एजेंसियों ने बढ़ाया भरोसा

नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने ताजा अनुमान में भारत की मजबूत स्थिति की पुष्टि करते हुए वर्ष 2026 और 2027 दोनों वित्तीय वर्षों के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह दर वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2026 में 3.1 प्रतिशत और 2027 में महज 3.4 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें, बढ़ता वैश्विक सरकारी



कर्ज और वित्तीय जोखिम अब भी दुनिया भर के बाजारों के लिए मुख्य चिंता बने हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में

निवेश बनेगा ग्लोबल ग्रोथ का इंजन: आईएमएफ ने अपने विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में हो रहे

भारी निवेश को वैश्विक विकास का एक प्रमुख सकारात्मक सहारा माना है। कंप्यूटिंग हार्डवेयर, अत्याधुनिक डेटा सेंटर और

एआई तकनीकों पर कंपनियों द्वारा किए जा रहे बड़े पूंजीगत व्यय से आर्थिक गतिविधियों को तेज रफ्तार मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, लंबी अवधि में एआई तकनीक विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन लागत घटाने और व्यापारिक दक्षता में सुधार करने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिसका सीधा लाभ आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा।

वर्ल्ड बैंक, मूडीज और एसएंडपी ने भी बढ़ाया भारत का ग्रोथ अनुमान: आईएमएफ से पहले दुनिया की तमाम शीर्ष वित्तीय व रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन पर मुहर लगा चुकी हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की

विकास दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह मूडीज रेटिंग्स ने भी हाल ही में अपने अनुमान में सीधे 1 प्रतिशत का बढ़ा इजाफा करते हुए इसे 7 प्रतिशत किया था।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास अनुमान में 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जबकि फिच रेटिंग्स ने भी अपने पूर्व के 6.4 प्रतिशत के अनुमान को संशोधित कर 6.9 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। सभी प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों के अनुमानों से स्पष्ट है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा मजबूती से बरकरार रखेगा।



न्यूज IN ब्रीफ

पलामू में 22 वर्षीय युवक की मौत गांव में पसरा मातम

पलामू : झारखंड के पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामघाट जोड़ा गांव में मंगलवार की सुबह एक 22 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी राजेश्वर माझी के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।



परिजनों ने सुबह दी घटना की जानकारी : प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब तीन बजे रोहित कुमार की मानसिक तनाव के बीच मौत हो गई। सुबह जब घर के अन्य सदस्य सोकर उठे, तो उन्होंने रोहित को घर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया। इसके बाद परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को दी गई सूचना : घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना सतबरवा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की ओर से घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। मौत के कारणों की जांच जारी : फिलहाल रोहित कुमार की मौत के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मानसिक तनाव की बात सामने आई है, लेकिन इसके वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त

मेदिनीनगर : सदर एसडीएम संजय पांडेय ने सतबरवा इलाके में औचक छापेमारी कर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को रंगे हाथ पकड़ा है। प्रशासन को इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध बालू माफियाओं और धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। मौके से ट्रैक्टर को जब्त करने के बाद एसडीएम ने इस पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन विभाग को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

हैदरनगर में श्रीकृष्ण की लीलाओं से भक्तिमय हुआ माहौल, वृंदावन के कलाकारों ने बांधा समां

हैदरनगर : शादीय नवरात्र के पावन अवसर पर हैदरनगर बाजार में श्रीकृष्ण रासलीला सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। वृंदावन से आए कलाकारों ने भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक लीलाओं का जीवंत मंचन कर श्रद्धालुओं को भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में सराबोर कर दिया। कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति से पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा और देर रात तक श्रद्धालु रासलीला का आनंद लेते रहे।

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद सदस्य संगीता देवी, अंचलाधिकारी संतोष कुमार और थाना प्रभारी तंजीलूल मनान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया। वृंदावन के कलाकारों ने भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। सजीव अभिनय, भावपूर्ण प्रस्तुति और भक्तिमय वातावरण ने दर्शकों का मन मोह लिया। पंडाल में मौजूद श्रद्धालु देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे।

इस अवसर पर पूजा समिति की ओर से राहुल कुमार सिंह, मुकेश मेहता, संतन चौधरी और हरिओम गुप्ता ने अतिथियों को माता की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन मुखिया संतोष सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मुखिया जितेंद्र सिंह ने किया।

आयोजन को सफल बनाने में अभिराज गुप्ता, राजू गुप्ता सहित पूजा समिति के अन्य सदस्यों की सराहनगी भूमिका रही। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और श्रीकृष्ण भक्ति से ओतप्रोत इस आयोजन ने नवरात्र के उत्सवी माहौल को और भी खास बना दिया।

विद्यालय के रसोई घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर व चूल्हे की चोरी

बरही : बीती रात उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कजरा के रसोई घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने गैस सिलेंडर और चूल्हे की चोरी कर ली। इस संघर्ष में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक निर्मल कुमार दास ने बरही थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, 12 अक्टूबर की सुबह करीब 10:30 बजे विद्यालय की रसोईया रसोई घर खोलने पहुंची तो ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जांच करने पर एक बड़ा एचपी गैस सिलेंडर और एक बड़ा चूल्हा गायब पाया गया। इसके बाद वरीय वदाधिकािरियों को घटना की जानकारी दी गई। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने आवेदन में बताया है कि विद्यालय गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित है। इस कारण यहां चोरी की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर चोरी गए सामान की बरामदगी और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

बोरोबिंग गांव में चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान

रामगढ़ : डॉ एस राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुकरीगढ़ा-लारी की ओर से 12 अक्टूबर को उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिए गए बोरोबिंग पंचायत में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत बोरोबिंग उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर से हुई। मुख्य अतिथि पंचायत की मुखिया वसंती देवी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की गई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर अभियान शुरू किया गया। गांव के विभिन्न कुओं और नालियों के आसपास भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। महाविद्यालय के प्राध्यापकों और बीएड तथा डीएलएड सत्र 2026-28 के प्रशिक्षुओं ने अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को साफ-सफाई बनाए रखने, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और आसपास के वातावरण को साफ रखने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने ह्हाथ से हाथ मिलाना है, गंदगी को दूर भगाना हैहू और ह्हम सबने यह ठाना है, स्वच्छ भारत बनाना हैहू जैसे नारों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छता को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की।

कार्यक्रम में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव एवं वरिष्ठ सदस्य डॉ संजय कुमार प्रभाकर, प्राचार्य डॉ. सुशील कुमार उपाध्याय, प्राध्यापक नयन कुमार मिश्रा, मोहम्मद परवेज अख्तर, इंदु कुमारी झा, सुप्रिया वर्मन, वक्शन कुमार, बाबूचंद प्रसाद, मुरारी कुमार दुबे और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक पिंदू कुमार पटेल उपस्थित रहे। बीएड एवं डीएलएड सत्र 2026-28 के प्रशिक्षुओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्ति गीतों के साथ डांडिया की धूम, झूम उठे श्रद्धालु

बिनय मिश्रा

रांची : राजधानी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना, भजन संध्या और डांडिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। भक्ति गीतों और डांडिया की धुन पर उपस्थित श्रद्धालु जमकर झूम और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया।

कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना और मां दुर्गा की आराधना के साथ हुई। इसके बाद आयोजित भजन संध्या में स्थानीय गायकों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। मधुर भजनों ने उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर परिसर में

देर तक भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।

भजन संध्या के दौरान जैसे ही डांडिया कार्यक्रम शुरू हुआ, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। भक्ति गीतों के साथ डांडिया की धुन पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। महिला, पुरुष और अन्य उपस्थित श्रद्धालु कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भक्ति और उल्लास के इस संगम ने पूरे आयोजन को खास बना दिया। नवरात्र के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना के साथ भजन, जागरण और डांडिया का आनंद लिया। पहाड़ी मंदिर में धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक उत्साह का भी अनूठा नजारा देखने को मिला।



पलामू में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़ा गया फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र

संवाददाता

पलामू : जिला के हरिहरगंज में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र पकड़ा गया है। पूरे मामले में प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ हरिहरगंज थाना में प्राथमिक की दर्ज करवाई गयी है जबकि पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के एकौनी गांव की रहने वाली विद्यापति देवी ने 25 सितंबर को एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान आवासीय प्रमाण पत्र जमा किया था। आवासीय प्रमाण पत्र की हरिहरगंज अंचल कार्यालय के द्वारा जांच की गयी तो चौकाने वाली जानकारी सामने आई। जिस आवासीय प्रमाण पत्र को विद्यापति देवी ने जमा किया, वह प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ था। जिस नंबर का आवास प्रमाण पत्र बनाया गया था वह



नंबर अंचल निरीक्षक के लॉगिन में लंबित था।पूरे मामले में प्रशासनिक टीम ने विद्यापति देवी से पूछताछ की गयी। जिसके बाद ये बात सामने आई कि प्रज्ञा केंद्र से प्रमाण पत्र को बनवाया गया था। विद्यापति देवी ने प्रशासनिक अधिकारी टीम को बताया कि प्रज्ञा केंद्र संचालक अब्दुल सलाम ने उसे आवासीय प्रमाण पत्र दिया था।हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत

पोद्दार ने बताया कि अंचल अधिकारी के आवेदन के आधार पर प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पूरे मामले में छानबीन शुरू की गई है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ा गया था। दरअसल कुछ दिनों पहले भी हरिहरगंज में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान एक फर्जी आवास प्रमाण पत्र पकड़ा गया था।

घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी

पीड़ित ने पुलिस से लगाई छानबीन की गुहार

बरकटड़ा : बरकटड़ा बाजार रोड़ स्थित एक मकान में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। इस बाबत बाजार रोड़ निवासी लक्ष्मण प्रसाद चौधरी ,पिता परमेश्वर प्रसाद ने बरकटड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया है कि रविवार 11-12 अक्टूबर की मध्य रात्रि को घर में लगे ताले को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया की रात को सभी लोग खाना खाकर बगल के कमरे में सोने चले गये, रात को लगभग दो बजे के करीब मेरे पिताजी कमरा को खुला देखकर शोर मचाने पर मैं और मेरे बड़े भैया उठकर गये। जाकर देखा कि बाहर के रूम में ताला ताला टूटा हुआ है, अंदर जाकर देखा

कि गोदरेज अलमीरा भी खुला पड़ा है। गोदरेज अलमीरा में रखा सभी सामान जमीन पर बिखरा हुआ है, साथ ही गोदरेज अलमीरा में रखा दोनों बहुओं की लगभग बीस लाख रुपए के जेवरात, पत्नी और पुत्री की लगभग दस लाख रुपए के जेवरात तथा पांच लाख रुपए नगदी समेत लगभग 30-35 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली गई है। मामले की सूचना मिलने पर बरकटड़ा थाना प्रभारी आशीष कुमार भगत ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली, साथ ही रांची से पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने साक्ष्य एकत्रित किया। पूर्व मुखिया बसंत साव ने कहा कि बरकटड़ा बाजार में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी घटना का उद्देदन नहीं हो पाया है. इससे चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आमजन के बीच भय का माहौल बना हुआ है।

दिव्यांगजनों को सहायक

सारण के पांच प्रखंडों में लगेने शिविर

संवाददाता

छपरा : दिव्यांगजनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सारण जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संवल के तहत सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की पहल तेज कर दी है। शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

इस अभियान के तहत सदर अनुमंडल सहित बनियापुर, दरियापुर, अमनौर और मांझी प्रखंड में निर्धारित तिथियों पर विशेष परीक्षण-सह-आवेदन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से संवल एवं दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण वितरण योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, दृष्टिबाधितों के लिए छड़ी, स्मार्ट छड़ी, बैसाखी, कृत्रिम अंग सहित अन्य आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रचार वाहन संबंधित क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को शिविरों की तिथि, स्थान और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद दिव्यांगजन इन योजनाओं से जुड़ सकें। जिला प्रशासन के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता का



न्यूनतम प्रतिशत 40 होना, बिहार का स्थायी निवासी होना तथा निर्धारित आय संबंधी पात्रता पूरी करना

आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, तस्वीर, निवास प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-

पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर शिविर में पहुंचना होगा। शिविरों का आयोजन सदर स्थित

साथ देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ। आकांक्षा सिन्हा ने नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के युवाओं तक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय को भी जरूरी बताया। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो। सुकुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों में निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा में प्रत्यक्ष संवाद और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी तकनीकी विषयों को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला अनुभव उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। मुख्य अतिथि विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से समाज के समावेशी विकास में अहम योगदान दे

संवाददाता
धनबाद : युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। फाउंडेशन की ओर से अधिकल्पन डिजाइन स्टूडियो के सहयोग से संचालित चार महीने के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (सीएडी) और कंप्यूटर-ग्रेडेड मैनुफैक्चरिंग (सीएमएम) प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 26 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। एयरपोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ाना है। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एयरपोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक विनोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो। सुकुमार मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो। सौम्या सिंह के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उद्योगों की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योगों के अनुरूप तकनीकी कौशल भी जरूरी है। उन्होंने कौशल विकास को युवाओं के भविष्य के साथ-

उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रचार वाहन रवाना

बुनियाद केन्द्र में 21 एवं 22 अक्टूबर, बनियापुर प्रखंड कार्यालय में 23 एवं 24 अक्टूबर, दरियापुर प्रखंड कार्यालय में 26 एवं 27 अक्टूबर, अमनौर प्रखंड कार्यालय में 28 एवं 29 अक्टूबर तथा मांझी प्रखंड कार्यालय में 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। सभी शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक संचालित होंगे।

जिला प्रशासन ने पात्र दिव्यांगजनों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर परीक्षण और आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। प्रशासन का लक्ष्य दिव्यांगजनों को जरूरत के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाना, उनकी गतिशीलता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना है।

धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग निर्धारित स्थल, अन्यत्र प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई

संवाददाता
पटना : विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में बिना पूर्व सूचना अथवा निर्धारित अनुमति के धरना-प्रदर्शन किए जाने के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग किया जाए। निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा, यातायात का सुचारू संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन किए जाने से शहर की

यातायात व्यवस्था बाधित होती है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रदर्शनों के कारण स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, जिले के वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं उनकी व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन एवं व्यवसाय से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही इस तरह की स्थिति में बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, स्कूली बच्चों तथा एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन में गंभीर कठिनाइयां

उत्पन्न होती हैं। इससे आवश्यक सेवाओं में विलंब होने के साथ आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संगठनों से अपील की है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग करें। साथ ही, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक शांति एवं आम नागरिकों की सुविधा बनाए रखने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र धरना-प्रदर्शन करने अथवा जारी निदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिस्ममत कार्रवाई की जाएगी।

आईआईटी आईएसएम धनबाद की पहल, 26 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के बाद मिला प्रमाण-पत्र